Rajasthan High Court: Vehicle Ownership Alone Cannot Make a Person an NDPS Act Accused

The Rajasthan High Court, in a case under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, has given a significant verdict. The court noted that just because someone is registered as the owner of a vehicle does not necessarily make him/her an accused under the NDPS Act. The prosecution will have to prove that the owner of the vehicle knew of the illegal activity or that they personally authorized the use of the vehicle to transport, conceal, or possess narcotic substances.

Rajasthan High Court's Important Observation

A bench presided over by Justice Anil Kumar Upman said the word 'knowingly' in Section 25 of the NDPS Act is of great significance. The court said that simply because a person has ownership of a vehicle does not make it a presumption that he or she knew someone was using it for an illegal purpose.

The court stated that there needs to be proof of the vehicle owner's knowledge, intent, or deliberate permission for the use of the vehicle for narcotics-related activities.

Key Highlights of the Judgment

Key Point	Details
Court	Rajasthan High Court
Judge	Justice Anil Kumar Upman

Related Law	NDPS Act
Important Provision	Section 25
Main Observation	Vehicle ownership alone is not sufficient to make someone an accused
Prosecution Requirement	Must establish knowledge or intentional permission
Important Word	“Knowingly”

Why Is This Judgment Important?

The judgment is important as it underlines that the ownership of a vehicle used in an alleged narcotics offence is not sufficient to make the owner liable for a criminal offence. The prosecution must prove the necessary connection between the owner and the illegal use of the vehicle.

The decision highlights the necessity of establishing the knowledge and intention in Section 25 of the NDPS Act cases. It also gives clarity in relation to when an offence may be charged to a vehicle owner if committed with the use of the vehicle.

Conclusion

The ruling of the High Court of Rajasthan lays down an important principle in the law that simply owning a vehicle does not make the owner liable under the NDPS Act. There must be evidence of knowledge or intentional permission for the use of the car in a drug-related crime.

MCQs

Q1. Which court delivered this important judgment?
A) Rajasthan High Court
B) Delhi High Court
C) Bombay High Court
D) Gujarat High Court
Answer: A) Rajasthan High Court

Q2. Which Act was involved in the case?
A) IPC
B) NDPS Act
C) Companies Act
D) Motor Vehicles Act
Answer: B) NDPS Act

RASonly

Q3. Which section was specifically discussed?
A) Section 20
B) Section 25
C) Section 37
D) Section 50
Answer: B) Section 25

Q4. What is not sufficient by itself to make someone an NDPS accused?
A) Vehicle ownership
B) Criminal confession
C) Drug possession
D) Proven knowledge
Answer: A) Vehicle ownership

राजस्थान हाईकोर्ट: केवल वाहन मालिक होने के आधार पर नहीं बनाया जा सकता NDPS एक्ट का आरोपी

राजस्थान हाईकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि केवल किसी व्यक्ति के वाहन का पंजीकृत मालिक होने मात्र से उसे NDPS एक्ट के तहत आरोपी नहीं बनाया जा सकता। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि वाहन मालिक को अवैध गतिविधि की जानकारी थी या उसने मादक पदार्थों के परिवहन, छिपाने या रखने के लिए वाहन के इस्तेमाल की जानबूझकर अनुमति दी थी।

राजस्थान हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी

न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि NDPS एक्ट की धारा 25 में इस्तेमाल किया गया 'जानबूझकर' **(Knowingly)** शब्द बेहद महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के पास वाहन का स्वामित्व होने मात्र से यह मान लेना उचित नहीं है कि उसे वाहन के अवैध गतिविधि में इस्तेमाल किए जाने की जानकारी थी।

कोर्ट ने कहा कि वाहन मालिक की जानकारी, मंशा या मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधि के लिए वाहन के इस्तेमाल की जानबूझकर दी गई अनुमति का प्रमाण होना आवश्यक है।

फैसले की मुख्य बातें

मुख्य बिंदु	विवरण
कोर्ट	राजस्थान हाईकोर्ट
न्यायाधीश	न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपमन
संबंधित कानून	NDPS एक्ट
महत्वपूर्ण प्रावधान	धारा 25

RASonly

मुख्य टिप्पणी	केवल वाहन का मालिक होना किसी व्यक्ति को आरोपी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं
अभियोजन पक्ष की आवश्यकता	मालिक की जानकारी या जानबूझकर दी गई अनुमति साबित करना आवश्यक
महत्वपूर्ण शब्द	“जानबूझकर” (Knowingly)

यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?

यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि किसी मादक पदार्थ से जुड़े कथित अपराध में इस्तेमाल किए गए वाहन का मालिक होना अपने आप में आपराधिक जिम्मेदारी तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभियोजन पक्ष को वाहन मालिक और वाहन के अवैध इस्तेमाल के बीच आवश्यक संबंध साबित करना होगा।

यह निर्णय NDPS एक्ट की धारा 25 से जुड़े मामलों में जानकारी और मंशा साबित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। साथ ही, यह स्पष्ट करता है कि किन परिस्थितियों में वाहन के मालिक को वाहन के माध्यम से किए गए मादक पदार्थ संबंधी अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

निष्कर्ष

राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले ने कानून के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को स्पष्ट किया है कि सिर्फ वाहन का मालिक होना व्यक्ति को **NDPS** एक्ट के तहत जिम्मेदार नहीं बनाता। वाहन का इस्तेमाल मादक पदार्थों से जुड़े अपराध में करने के लिए मालिक की जानकारी या जानबूझकर दी गई अनुमति का प्रमाण आवश्यक है।

MCQs

Q1. यह महत्वपूर्ण फैसला किस हाईकोर्ट ने दिया है?
A) राजस्थान हाईकोर्ट
B) दिल्ली हाईकोर्ट
C) बॉम्बे हाईकोर्ट
D) गुजरात हाईकोर्ट
उत्तर: **A)** राजस्थान हाईकोर्ट

Q2. यह मामला किस एक्ट से संबंधित था?
A) IPC
B) NDPS एक्ट
C) कंपनी अधिनियम
D) मोटर वाहन अधिनियम
उत्तर: **B) NDPS** एक्ट

Q3. फैसले में किस धारा पर विशेष रूप से चर्चा की गई?
A) धारा 20
B) धारा 25
C) धारा 37

RASonly

D) धारा 50
उत्तर: **B)** धारा **25**

Q4. किसी व्यक्ति को **NDPS** एक्ट का आरोपी बनाने के लिए अपने आप में क्या पर्याप्त नहीं है?
A) वाहन का मालिक होना
B) आपराधिक स्वीकारोक्ति
C) मादक पदार्थों का कब्जा
D) साबित जानकारी
उत्तर: **A)** वाहन का मालिक होना

Supreme Court Upholds School Entry Restrictions in U.P. & Rajasthan

On September 3, 2026, the Supreme Court refused to address a petition against the Uttar Pradesh and Rajasthan governments' ban on journalists, social media influencers, and civil rights activists accessing government schools. The restrictions also cover photography, videography, interviews, audio recording, and livestreaming.

Key Highlights

Point	Details
Court	Supreme Court of India
Date	September 3, 2026
States	Uttar Pradesh and Rajasthan

Restrictions	Entry, photography, videography, interviews, and livestreaming
Petitioner	Priya Mishra
Constitutional Provision	Article 32

Why Is It Important?

The concern is significant as it could impact independent reporting and public exposure of government schools. Documentation can help highlight the condition of classrooms, toilets, drinking-water facilities, electricity, and other basic infrastructure.

‘School Thik Karo’ Campaign

The plea came soon after the ‘School Thik Karo’ campaign by CJP, which seeks to audit and improve neglected infrastructure in government schools, especially in rural areas.

Conclusion

The Supreme Court's decision means that the challenged restrictions will continue for now. The issue is significant as it brings to light the balance between security at school and public accountability. Continuing to follow administrative rules with proper documentation can help identify infrastructure gaps.

MCQs

1. Which court declined to entertain the plea?
A. High Court
B. Supreme Court
C. District Court
D. NGT
Answer: B. Supreme Court

2. Which states imposed the restrictions?
A. Rajasthan and Haryana
B. U.P. and Bihar
C. U.P. and Rajasthan
D. Rajasthan and Gujarat
Answer: C. U.P. and Rajasthan

3. Under which Article was the petition filed?
A. Article 14
B. Article 19
C. Article 21
D. Article 32
Answer: D. Article 32

RASonly

4. What is the aim of the ‘School Thik Karo’ campaign?
A. Teacher recruitment
B. School infrastructure improvement
C. Sports promotion
D. Digital examinations
Answer: B. School infrastructure improvement

सुप्रीम कोर्ट ने यू.पी. और राजस्थान में स्कूल प्रवेश प्रतिबंध बरकरार रखे

3 सितंबर, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों द्वारा सरकारी स्कूलों में पत्रकारों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इन प्रतिबंधों में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइवस्ट्रीमिंग भी शामिल हैं।

मुख्य बिंदु

बिंदु	विवरण
न्यायालय	भारत का सुप्रीम कोर्ट
तिथि	3 सितंबर, 2026
राज्य	उत्तर प्रदेश और राजस्थान
प्रतिबंध	प्रवेश, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू और लाइवस्ट्रीमिंग
याचिकाकर्ता	प्रिया मिश्रा
संवैधानिक प्रावधान	अनुच्छेद 32

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

यह चिंता महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सरकारी स्कूलों की स्वतंत्र रिपोर्टिंग और सार्वजनिक जानकारी प्रभावित हो सकती है। दस्तावेजीकरण से कक्षाओं, शौचालयों, पेयजल सुविधाओं, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे की स्थिति को सामने लाने में मदद मिल सकती है।

‘स्कूल ठीक करो’ अभियान

यह याचिका CJP के ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के तुरंत बाद आई, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, उपेक्षित बुनियादी ढांचे का ऑडिट करना और उसमें सुधार करना है।

RASonly

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब है कि फिलहाल चुनौती दिए गए प्रतिबंध जारी रहेंगे। यह मुद्दा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्कूलों की सुरक्षा और सार्वजनिक जवाबदेही के बीच संतुलन को सामने लाता है। उचित दस्तावेजीकरण प्रशासनिक नियमों का पालन करते हुए बुनियादी ढांचे की कमियों की पहचान करने में मदद कर सकता है।

MCQs

1. याचिका पर विचार करने से किस न्यायालय ने इनकार किया?
A. हाई कोर्ट
B. सुप्रीम कोर्ट
C. जिला न्यायालय
D. NGT
उत्तर: **B.** सुप्रीम कोर्ट

2. किन राज्यों ने प्रतिबंध लगाए?
A. राजस्थान और हरियाणा
B. यू.पी. और बिहार
C. यू.पी. और राजस्थान
D. राजस्थान और गुजरात
उत्तर: **C.** यू.पी. और राजस्थान

3. याचिका किस अनुच्छेद के तहत दायर की गई थी?
A. अनुच्छेद 14
B. अनुच्छेद 19
C. अनुच्छेद 21
D. अनुच्छेद 32
उत्तर: **D.** अनुच्छेद **32**

4. 'स्कूल ठीक करो' अभियान का उद्देश्य क्या है?
A. शिक्षक भर्ती
B. स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार
C. खेलों को बढ़ावा देना
D. डिजिटल परीक्षाएं
उत्तर: **B.** स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार

RASonly